

प्रेषक,

अर्जुन सिंह

अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक

नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन

उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 01 जनवरी, 2011

विषय:- अनुदान सं०-27 के आयोजनागत पक्ष की केन्द्र पुरोनिधानित योजना "प्रोजेक्ट एलीफेंट" के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में वित्तीय स्वीकृति.  
महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-नि०-956/3-6 (प्रोजेक्ट एलीफेंट) दिनांक 10 जनवरी, 2011 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-1-11/2009-(PE), दिनांक 09 सितम्बर, 2009 तथा भारत सरकार के पत्र संख्या-1-11/2009-(PE), दिनांक 05 अक्टूबर, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अन्तर्गत संचालित केन्द्र पुरोनिधानित योजना "प्रोजेक्ट एलीफेंट" (100 प्रतिशत केन्द्रांश) के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 हेतु पूर्व में निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों के अतिरिक्त प्रस्तर-2 में इंगित तालिका में मदवार इंगित ₹ 15,76,000/- (₹ पन्ध्र लाख सित्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि वर्णित योजना हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदित कार्ययोजनागत स्वीकृत कार्यों/मदों पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों के क्रियान्वयन के लिए न किया जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों एवं मदों में उसी मात्रा में किया जाय, जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हो एवं व्यय करते समय भारत सरकार द्वारा बताई गई शर्तों एवं निर्गत निदेशों की अनुपालन भी सुनिश्चित की जाय.
2. उक्त स्वीकृति व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं०-187/XXVII(1)/2010, दिनांक 30 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति/यथास्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय. शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण निर्धारण प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1(लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मेनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.
3. यह संज्ञान में आया है कि धनराशि विभागाध्यक्षों के निवर्तन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है. अतः आपके निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो, परन्तु यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि का आहरण वास्तविक मांग आधार पर किशतों में किया जाय.
4. आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी०एम०-17 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा.
5. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय.
6. अनुदान के अन्तर्गत होने वाली सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-प्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो.
7. बी०एम०-13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 20 तारिख तक पूर्ण माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय.
8. जो निर्माण कार्य आरम्भ किये जा चुके हैं, के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत कार्य, आगणन की धनराशि, निर्गत वित्तीय स्वीकृति इत्यादि का विवरण वित्त विभाग के शासनादेश-485/XXVII(1)/2009, दिनांक 16 जुलाई, 2009 द्वारा निर्धारित किये गये प्रक्रियानुसार निर्धारित प्रपत्रों पर प्रशासकीय विभाग, नियोजन विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.
9. मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं०-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी.

क्रमशः.....2

10. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.
12. जिन कार्यों/मदों हेतु भारत सरकार में स्वीकृति नहीं है एवं जहां स्वीकृत कार्यों/मदों में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राशि से अधिक स्वीकृति निर्गत हो गई हो उसमें सम्बन्धित उपलब्ध धनराशि तथा अप्रयुक्त धनराशि को समय से समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.
13. निर्माण कार्यों के लागत व समय वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्यवाही व संचन अनुश्रवण किया जायेगा एवं इस हेतु बजट मैनुअल के प्रस्तर-211(डी) की अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी.
14. विभागाध्यक्ष द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में तथा हर माह की 10 तारीख तक वित्त एवं नियोजन विभाग को केन्द्र सहायतित/बाह्य सहायतित योजनाओं में अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष केन्द्रांश की धनराशि तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई धनराशि का विवरण उपलब्ध कराएंगे. उक्त सूचना के अभाव में वित्तीय अधिकारों पर रोक लगा दी जायेगी. केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले अवशेष धनराशि का विवरण भी प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा.
15. यह वित्तीय स्वीकृति इस शर्त/प्रतिबन्ध के अधीन भी है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में अगली वित्तीय स्वीकृति तभी निर्गत की जायेगी, जबकि निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रत्येक योजना के सम्बन्ध में स्टेटस रिपोर्ट अर्थात् योजना कब प्रारम्भ की गई, कितने वर्षों के लिए योजना है, योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य कितना है तथा लक्षित योजना के सापेक्ष कितना भौतिक लक्ष्य अभी प्राप्त हो चुका है एवं कितना शेष है, आदि के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा यह भी कि गत वित्तीय वर्ष 2009-10 में निर्गत की गई समस्त वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा.
16. योजना में अपेक्षित वित्तीय स्वीकृति/धनराशि अवमुक्त तभी की जायेगी जब सम्पूर्ण परियोजना/कार्ययोजना मय योजना अवधि, कुल लागत, वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य, outcome/impact के लक्ष्य/अनुमान, चयनित कार्यों का विवरण आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट/प्रस्ताव पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो.
17. उपरोक्त वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन भी है कि पूर्व में निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों का प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा पुनर्वैध की गई धनराशि की पुष्टि भी कराते हुए तदसम्बन्धी सूचना शासन को उपलब्ध करा दी जायेगी.

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्यय अनुदान सं०-27 के लेखाशीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110-वन्य जीवन परिरक्षण 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 0103-"प्रोजेक्ट एलीफेंट" हेतु निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार संगत मदों के नामे डाला जायेगा:-

(धनराशि ₹ हजार में)		
मानक मद	आय-व्यय प्रावधान	वर्तमान वित्तीय स्वीकृति
2	3	4
25- लघु निर्माण कार्य	12000	1571
29- अनुरक्षण	20000	5
योग	57200	1576

(वर्तमान वित्तीय स्वीकृति ₹ पन्द्रह लाख छियहत्तर हजार मात्र)

3. ये आदेश वित्त विभाग के अ०शा०सं०-383(P)/XXVII(1)/2010, दिनांक 25 जनवरी, 2011 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं.

भवदीय

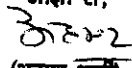
(अर्जुन सिंह)

अपर सचिव

संख्या-166 (1)/X-2-2011, तदुद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
2. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, शिविर कार्यालय-देहरादून.
5. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून.
6. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून.
7. निदेशक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, उत्तराखण्ड, देहरादून.
8. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
9. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
10. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल.
11. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
12. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्य, देहरादून.
13. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
14. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
15. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
16. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
17. गार्ड फाइल.

आज्ञा से,  
  
(अहमद अली)  
अनु सचिव